THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Is it the sense *at* the House that this Resolution should be carried over to the next Seasson?

HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay. This will be done.

STATEMENTS BY MINISTERS

Price policy for Raw Jute for 1994-95 season

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): The Government of lndia has fixed the Minimum Support Price (MSP) for TD-5 grade of raw jute in Assam for 1994-95 season at Rs. 470 per quintal. This marks an increase of Rs 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. The corresponding Minimum Support Prices of other varieties and grades of raw jute shall be fixed by the Jute Commissioner of India. Ministry of Textiles, in the light of normal market price differentials.

The Jute Corporation of India (ICD will undertake price support operations in raw jute as and when required. Adequate funds will be provided in time to ICT to perform its functions efficiently.

The increase in Minimum Support Price is expected to encourage the farmers to invest more in jute cultivation and raise the production/productivity of raw jute.

THE VICE-CHARMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Now. clarifications. I have some names in front of me. Mr. John F. Fernandes. Not here Mr. Satya Prakash Malaviya. Not here. Dr. Biplab Dasgupta. Not here. Mr. N. Giri Prasad.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the statement made by the hon Minister on the price for jute is highly disappointing. I say this because the increase is only Rs. 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. As everybody knows, the inflation rate is more than 10 per cent. Even if we take it as the basis for calculation, the Government should have increased it atleost by Rs. 50. Why has the Government fixed it only at Rs. 20? Just sometime before, the Minister for Civil Supplies was saying that they were increasing the price of agricultural produce at the rate of Rs. 55, but it seems this doesn't apply to raw jute. In my State, of course, there is a small area in the north coastal districts like Srikakulam where jute is grown but, as far as I understand, the per acre yield is very low and the price also is very low. In this background, in order to help the jute growers ,the Govemment must come forward to increase it at leas; by Rs. 50. Otherwise it will not be remunerative.

Madam, you please see the last paragraph of the statement: "The increase in Minimum Support Price is exepcted to encouarge the farmers *to* invest more in jute cultivation and raise the production/ productivity of raw jute." With this meagre increase of Rs. 20, can you expect to achieve this aim of encouraging the farmers to invest more ? On what basis can they invest? There should be some income to invest. There is no income. It does not give any income; it does not even neutralize the inflationary pressure Then how can they increase the production/productivity? So I request the Minister to consider raising the price at least to that level.

I think, even after increasing the price, the Agriculture Ministry needs to consider whether it is not necessary to divert part of this cultivation to other remunerative crops. T am afraid, in spite of the best efforts being made in most of the places, jute cultivation is not proving to be remunerative. That is why they can advise or persuade the peasants, wherever they can grow alternative crops, to shift to some other crops, besides increasing the iute price a bit more.

Thank you.

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उप सभा ध्यक्ष महोदया माननीय कृषि मं जी ने जो अभी वक्तव्य दिया इस

सिर्फ एक ग्रेड टी.डी–5 की चर्चा की है और 450 से 20 रुपये मात्र इसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर इसको 470 रुपया करने की घोषणा उन्होंने इस अंदाज में की है जैसे उन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया हो। केवल 5 प्रतिशत से भी कम वृद्धि है यह। यदि हम मुद्रा स्फीति को लें तो एक वर्ष में 10 से लेकर 15 प्रतिशत मुद्रा-स्फीति हो जाती है। इसकी क्षति-पूर्ति करने के लिए भी यह समर्थन मूल्य की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। यह अन्याय अकेले किसानों के साथ क्यों होता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि बात अधूरे में क्यों छोड़ देते हैं? केवल टी डी–5 के मूल्य की घोषणा क्यों की, बाकी ग्रेडों के लिये घोषणा क्यों नहीं की? राज्य सरकारें ढिंढोरा पीटती रहती हैं कि कृषि को हम इतनी प्राथमिकता देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं उधर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यदि उन्हें बात करनी हो तो वे सदन से बाहर जा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको निर्देश दें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) कृषि मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री सोमपाल : पर मैं सत्ताधारी सदस्यों से भी चाहता हूं कि वे सुनें।

उपसभाध्यक्ष : मंत्रीगण पहले माननीय सदस्य की बात को सुनें।

श्री सोमपाल : यह इस बात का प्रमाण है कि सत्ताधारी पक्ष के लोग इस संबंध में कितने गंभीर हैं। केवल 5 प्रतिशत से भी कम मूल्य वृद्धि की घोषणा केवल मुद्रा-स्फीति की क्षति-पूर्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं है और वह भी एक ग्रेड की बाकी को अधूरे में छोड़ दिया। यह तथ्य है उपसभाध्यक्ष महोदया, कि जूट की खेती और जूट का उद्योग भारत का परंपरागत उद्योग रहा है और विश्व का प्राचीनतम उद्योग और खेती जूट की रही है। इसकी खेती और विनिर्मित उत्पादों में भारत सब से अग्रणी रहा है। भारत का पटसन उद्योग भी खेती ही नहीं और जैसा कि मैंने कहा विश्व का सर्वाधिक विकसित और प्राचीनतम उद्योग रहा है। कच्चे जूट और जूट से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में भी विश्व व्यापार में भारत की अहम भूमिका रही है। और सब से ज्यादा उत्पादन और सब से ज्यादा निर्यात भारत ही करता रहा है। इस जूट की खेती और इसके उद्योग में लगे लोगों की इतनी बड़ी संख्या रही है कि रोजगार प्रदान करने में विशेष कर उन पिछड़े प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर लोगों को जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो बहुत गरीब लोग थे उनकी आजीविका का सदा से प्राचीन काल से, यह साधन रहा है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आया है, और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं, कि कृषि समिति के साथ जब हम बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दौरा करने गए मई 1991 में और हमने वहां पर इसका जो पटसन निगम है इसके कार्य कलाप की समीक्षा की, जूट की खेती की समीक्षा की तो हमने पाया कि समर्थन मूल्य मात्र घोषित करके सरकार सो जाती है। पटसन निगम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, उनके पास राशि नहीं थी समर्थन मूल्य के ऊपर जितना उत्पादन किसान करते थे उसको खरीदने के लिए, जिन मिलों को उस पटसन निगम का यह माल आपूर्ति किया हुआ था उसका भुगतान मिलें नहीं देती थीं और सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की। तीन वर्ष लगातार 1990-91, 1991-92 और 1992-93 समर्थन मूल्यों के आधार पर खरीद बिल्कुल विकलांगित रही है, एकदम निरस्त पड़ी रही है। कोई समर्थन इन्होंने किसानों को नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि इसका क्षेत्रफल गंभीर रूप से घटा है, इसका उत्पादन घटा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष महोदया, ये सारे प्रश्न ही हैं। ये सारे ही प्रश्न हैं।

उपसभाध्यक्ष संक्षेप में करें।

श्री सोमपाल : अब वह विषय संक्षिप्त है नहीं। यहां किसान की बात तो बहुत संक्षिप्त

कर देते हैं और जो 3 प्रतिशत लोग हैं, उनके ऊपर घंटों चर्चा करते हैं ।

लेकिन उनके पास साधन नहीं था, उसी के कारण न उसका अनुसंधान हो पाया न उसका उत्पादन बढ़ पाया, न किसानों को समर्थन मूल्य मिला और उससे क्षेत्रफल भी कम हो रहा है, उत्पादन भी कम हो रहा है ।

मैं एक नई बात कहना चाहता हूं कि अभी-अभी जर्मनी में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें भारत के जूट विनिर्मित आधुनिक किस्म के वस्त्र और उनके डिजाइनों का बड़ा भारी स्वागत किया गया यूरोप के बाजार में और जब से पर्यावरण के प्रति विश्व भर में जागृति आई है, खास तौर से रियो कांफ्रेंस के बाद तो पर्यावरण मैत्रिक उत्पादों की मांग आगे बहुत बढ़ने वाली है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जितने मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, एक तो उन्होंने समर्थन मूल्य एक ग्रेड का ही क्यों घोषित किया और इतना कम क्यों घोषित किया कि मुद्रा-स्फीती की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी वह पर्याप्त नहीं है ? इसके अनुसंधान के विषय में क्यों प्रगति नहीं हो पा रही, इसका आप क्या करने जा रहे हैं ? इसका निर्यात क्यों घट रहा है, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? इसका उद्योग-धंधा बंद हो रहा है विश्व में सब से बड़ा हमारा था वह सारा शिफ्ट हो कर पूर्वी बंगाल में चला गया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? इसका क्षेत्रफल घट रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? नई किस्मों के विकास के लिए आप क्या करना चाहते हैं और पिछले तीन वर्षों में इसकी खरीद नहीं की गई, क्या इस वर्ष भी आप केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके उसकी खरीद का प्रबन्ध करेंगे या नहीं करेंगे ? यदि नहीं तो जूट की खेती, जूट का उद्योग और इसका निर्यात इस सब का भविष्य अंधकारमय है और इसकी बहुत बड़ी क्षति भारत को उठानी पड़ सकती है ?

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): मैडम, बहुत सी बातें सोमपाल जी कह चुके हैं। एक तो सवाल यह है कि एक वैरायटी की जूट टी०डी०-5 और वह भी आसाम के लिए क्यों, सब वैरायटी के जो जूट थे, किसानों की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से यह मांग थी मुद्रा-स्फीति को मद्देनजर रखते हुए और जो किसान जूट की खेती कर रहे हैं पटसन की कीमत बढ़ाने के लिए यह मांग की गई थी कि इस साल कम से कम 10 परसेंट की बढ़ोतरी हो। अभी कुछ देर पहले हम मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहे थे। उस समय कृषि मंत्री भी उपस्थित थे और उन्होंने किस तरह से प्रोक्यूरमेंट प्राइस बढ़ायी है, वह इसके लिए शाबाशी ले रहे थे। तो जो जूट के किसान हैं, पटसन के किसान हैं, उनके साथ यह अन्याय क्यों है ? उपसभाध्यक्ष महोदया, जो उनकी मुद्रास्फीति की दर है और उनके इनपुट्स के दरों में जो वृद्धि हुई है, उसको ये ध्यान में नहीं रखते और आप बहादुरी दिखा रहे हैं जबकि क्या यह सच नहीं है कि आपके पास बंगाल की राज्य सरकार ने यह मांग की है कि टी०डी०-5 की मिनिमम प्रोक्यूरमेंट प्राइस 700 रुपए क्विंटल होनी चाहिए। बंगाल के मुख्य मंत्री की तरफ से क्या आपके पास यह मांग नहीं भेजी गयी है ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जूट इज ए सीजनल क्रॉप।

†شری محمد سلیم (مغربی بنگال): میڈم، بہت سی باتیں سومپال جی کہہ چکے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ایک ورائٹی کی جوٹ ٹی۔ ڈی۔ ۵ اور وہ بھی آسام کے لیے کیوں سب ورائٹی کے جوٹ تھے۔ کسانوں کی اور سے اور راجیہ سرکاروں کی اور سے یہ مانگ تھی اور افسوس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور جو کسان جوٹ کی کھیتی کر رہے ہیں جوٹ کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ مانگ کی گئی تھی کہ اس سال کم سے

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

لم۔ ا پارلیمنٹ کی بڑھوتری ہو۔ ابھی کچھ دیر
پہلے ہم مدیرا اسفیتی کے بارے میں بات
کر رہے تھے۔ اس سمے کرشی منتری بھی اپستھت
تھے اور انہوں نے کس طرح پروکیورمنٹ
پرائس بڑھائی ہے۔ وہ اس کے لیے بہادری
لے رہے تھے۔ تو جو جوٹ کے کسان ہیں۔
پٹسن کے کسان ہیں ان کے ساتھ یہ انیائے
کیوں ہے۔ اپ سبھا ادھیکش مہودیہ۔ جو ان کی
مدرا اسفیتی کی در ہے اور ان کے انپٹس
کے دام میں جو ورِدھی ہوئی ہے۔ اس
کو یہ دھیان میں نہیں رکھتے اور آپ بہادری
لے رہے ہیں۔ جبکہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ
کے پاس بنگال کی راجیہ سرکار نے یہ مانگ کی تھی
کہ جی۔ ڈی ۵ کی سنیم پروکیورمنٹ پرائس
۔۔۔ روپے کونٹل ہونی چاہیے۔ بنگال کے
۔۔۔ منتری کی طرف سے کیا آپ کے پاس یہ
نہیں بھیجی گئی ہے۔

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या [कृषि लागत एवं मल्य आयोग की संस्तुति, इसके ऊपर सरकार ने ली है क्योंकि यह बहुत ही कम मूल्य है और परिणाम यह है कि दूसरी जो अधिक आय वाली फसलें हैं, उनमें क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और जूट का कम होता जा रहा है। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो क्या सरकार उसको संदर्भित करना चाहेगी लागत एवं मल्य आयोग को ?

श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, जूट के किसान का अभी तक जो रोना था, वही रोना वे रो रहे हैं, चाहे वे पूर्वी भारत के हों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हों चाहे बिहार के हों या उत्तर बिहार के हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों और चाहे बंगाल या आसाम के हों। आप इसे ध्यान में नहीं रख रहे हैं जबकि आजादी के समय आपका यह वायदा था कि पटसन के किसान के जो इंटरेस्ट्स हैं, उसको आप देखेंगे।

महोदया, मेरा अगला सवाल यह है कि अपने स्टेटमेंट के दूसरे पैरा में आपने कहा है कि–

شری محمد سلیم: مہودیہ جوٹ کے کسان کا
ابھی تک جو رونا تھا۔ وہی رونا وہ رو رہے
ہیں۔ چاہے وہ پوروی بھارت کے ہوں۔
اتر پوروی اکشیتر کے ہوں۔ چاہے بہار کے
ہوں یا اتر بہار کے ہوں۔ پوروی اتر پردیش
کے ہوں اور چاہے بنگال یا آسام کے ہوں۔
آپ اسے دھیان میں نہیں رکھ رہے ہیں جبکہ
آزادی کے سمے آپ کا یہ وعدہ تھا کہ پٹسن کے
جو انٹرسٹس ہیں اس کو آپ دیکھیں گے۔
مہودیہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ
کے دوسرے پیرا میں آپ نے کہا ہے کہ۔

The Jute Corporation of India will undertake price support operations in raw jute as and when required. When?

टाईमिंग क्या है

ٹائمنگ کیا ہے۔

you allow the middlemen to procure it, compel the peasants to have distress sales. And now you are declaring an increase so that the middlemen will be

†[ ] Transliteration in Arabic Script

[श्री मोहम्मद सलीम]

benefited. Each and every year the Government and the jute growers are demanding that you declare the procurement price well in advance, so that they can procure directly from the small jute growers.

लेकिन क्या आप करते हैं? यह हर वर्ष की कहानी है, चाहे आसाम हो, बंगाल हो या बिहार हो जे.सी.आय. यह कहती है कि किसान जब जूट लेकर बाजार में आते हैं, मंडी में आते हैं तो जे.सी.आय. कहती है कि हमारा पैसा अभी सेंक्शन नहीं हुआ है। फिर जो जूट के बड़े-बड़े कारोबारी हैं, जो जूट के मालिक हैं, उनके दलाल उसे डिस्ट्रेस सेल से खरीद लेते हैं और तब आप घोषणा करते हैं। उसके बाद रुपया देते हैं ताकि मिडिलमैन के जरिए उनको फायदा पहुंचे पर किसानों को फायदा नहीं पहुंचे। तो कब तक यह कहानी चलती रहेगी आपको जूट सीजन से पहले, वैल इन एडवांस घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा यह जो बढ़ोतरी है, वह हर वैरायटी में होनी चाहिए थी।

अगली बात, हमारे यहां बंगाल में पंचायती राज सिस्टम है। हमारी मांग है कि आपकी जे.सी.आय. जो प्रोक्यूरमेंट करे, वह लोएस्ट लेवल पर जो पंचायत की मशीनरी है, उसको साथ लेकर करे जिससे जो रियल ग्रोअर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। सही मायने में आपका प्रोक्यूरमेंट भी होगा और जो फायदा आप किसान को देना चाहते हैं, अगर वह आपके ध्यान में है, तो वह उन किसानों को मिलेगा। इसके लिए पंचायत बोडीज को आपको कॉफिडेंस में लेना चाहिए। उनके साथ लियाजन रखना चाहिए।

You; should have a close liaison with the Panchayati Raj bodies in Bengal and in other parts so that

ताकि जूट प्रोक्यूरमेंट के समय आसानी हो और किसानों को किफायत भी हो। इस सिलसिले में क्योंकि आपने कहा है एज एंड व्हैन रिक्वायर, मैं पूछना चाहूंगा कि इस साल आपका जे.सी.आय. के लिए बजटरी प्रोविजन क्या है जूट प्रोक्यूरमेंट के लिए और पिछले साल से वह कितना बढ़ा हुआ हैं और आप कब रिवाइज करेंगे?

अगला मेरा सवाल यह है कि किसान जो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, उसके बारे में पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ध्यान रखे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में मैं पहले भी पूछ चुका हूं और कह चुका हूं कि आप क्राप्स बाजार में आने से पहले उसका अनाउंसमेंट करें। आप यहां बोल रहे है कि दूसरी तमाम वैरायटीज के बारे में जे.सी. आय. फैसला करेगी, क्यों? आपके स्टेटमेंट में यह है कि टी.डी.5 में आप बढ़ा रहे हैं और कारेसपोंडिंग

لیکن آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہر ورش کی
کہانی ہے۔ چاہے آسام ہو۔ بنگال ہو یا بہار
ہو۔ جے۔ سی۔ آئی۔ یہ کہتی ہے کہ کسان جب
جوٹ لیکر بازار میں آتے ہیں۔ منڈی میں آتے
ہیں۔ تو جے۔ سی۔ آئی۔ کہتی ہے کہ ہمارا پیسہ
ابھی سینکشن نہیں ہوا ہے۔ پھر جو جوٹ کے
بڑے بڑے کاروباری ہیں۔ جو جوٹ کے
مالک ہیں۔ ان کے دلال اسے ڈسٹریس سیل
سے خرید لیتے ہیں اور تب آپ گھوشنا
کرتے ہیں۔ اس کے بعد روپیہ دیتے ہیں تاکہ
مڈل مین کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچے اور
کسانوں کو فائدہ نہیں پہنچے۔ تو کب تک یہ
کہانی چلتی رہے گی۔ آپ کو جوٹ سیزن سے
پہلے۔ ویل ان ایڈوانس گھوشنا کرنی چاہئے
اس کے علاوہ یہ جو بڑھوتری ہے۔ وہ ہر

[ ] Transliteration in Arabic Script.

ویرائٹی میں ہونی چاہیے تھی۔
اگلی بات ہمارے یہاں بنگال میں پنچایتی راج سسٹم
ہے۔ ہماری مانگ ہے کہ آپ کی جے۔سی۔آئی جو پروکیورمنٹ
کرے۔ وہ لو ایسٹ لیول پر جو پنچایت کی مشینری ہے
اس کو ساتھ لے کر کرے جس سے کہ جو ریئل گروارس
ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ صحیح معنی میں آپکا پروکیورمنٹ
بھی ہوگا اور جو فائدہ آپ کسان کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ
بیچ کے دھیان میں رہے تو وہ ان کسانوں کو ملے گا۔
اس کے لیے پنچایت باڈیز کو آپکو کانفیڈینس میں لینا چاہیے
ان کے ساتھ لیازان رکھنا چاہیے۔

You should have a close liasion with the Panchayati Raj bodies in Bengal and in other parts so that

تاکہ جوٹ پروکیورمنٹ کے سمے آسانی ہو اور کسانوں
کو کفایت ملا ہو۔ اس سلسلے میں کیونکہ آپ نے کہا ہے
"لیبر انٹینسو ٹیکسٹائل ریکنائز"۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس
سال ایک لاکھ جے۔سی۔آئی کے لیے بجٹری پروویزن کیا
ہے جوٹ پروکیورمنٹ کے لیے اور پچھلے سال سے وہ
کتنا بڑھا ہوا ہے اور آپ کب ریلائز کریں گے۔ اگلا میرا
سوال یہ ہے کہ کسان ہے اور وہ جوٹ ڈسٹریس سیل
کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے سے ہی گورنمنٹ آف انڈیا
کو دھیان رکھے۔ منیمم سپورٹ پرائس کے سمبندھ میں
میں پوچھنا چاہوں گا پوچھ چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اپنی
بازار میں آنے سے پہلے اسکا اناؤنسمنٹ کریں۔ آپ یہاں
بول رہے ہیں کہ دوسری تمام ورائٹیز کے بارے میں
جے۔سی۔آئی فیصلہ کرے گی۔ کیوں۔ آپ کے اسٹیٹمنٹ

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

Minimum support price of every variety and grade of raw jute shall be fixed by the JCI and the Ministry of Textiles in the light of the normal market price differentials. Why not in the light of the rate of inflation and the price of agricultural inputs?

आप मार्केट को आर्टीफिसियली कंट्रोल करते हैं मिडिलमैन और मिल ओनर्स के जरिए। तो आप क्या ऐसे नार्मस लेंगे कि आटोमेटिकली जैसे हमारे डी. ए. उसी के अनुसार बढ़ते हैं कर्मचारियों के या अफसरों के तो उसानुससार इण्डेक्स देखकर के, जो प्राइस इण्डेक्स और पर्टिकुल उसमें एग्रीकल्चर इनपुटस का है, उसके लिहाज से वह प्राइस बढ़ेगी और बढ़नी ही चाहिए।

यह हमारी मांग है और आपसे हमारे ये सवाल थे। हम चाहते हैं कि आप इनका स्पष्ट जवाब दें।

شری محمد سلیم "جاری": آپ مارکیٹ کو آرٹیفیشیلی
کنٹرول کرتے ہیں مڈل مین اور مل آنرس کے ذریعے
تو آپ کیا ایسے نارمس لیں گے کہ آٹومیٹکلی جیسے ہمارے
ڈی۔اے۔ بڑھتے ہیں کرمچاریوں کے یا افسروں کے
تو اس انوسار انڈیکس دیکھ کر کے۔ جو پرائس انڈیکس
اور پرٹیکلر اس میں ایگری کلچر انپٹس کا ہے۔ اس کے
لحاظ سے وہ پرائس بڑھے گی اور بڑھنی ہی چاہیے۔
یہ ہماری مانگ ہے اور آپ سے یہ سوال ہمارے تھے۔ ہم
چاہتے ہیں کہ آپ انکا سپشٹ جواب دیں گے۔ "ختم"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Shri Somappa R. Bomai, not here.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Madani, we are now going to grow different grades of jute within a month or two. If the Government doesno't fix the support price, then, farmers will not grow jute. There will be less jute production. I want to know whether the Government is going to fix the support price for other varieties of jute or not before June

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री अरबिन्द नेताम): मैडम, डिप्टी चेयरपरसन, माननीय सदस्यों ने जो कुछ स्पष्टीकरण चाहा है, मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों को मैं क्लीयर कर सकूं। जैसा कि पूरा सदन जानता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यह सी०ए०सी०पी०, कमीशन फोर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, यह सभी पहलुओं पर पहले विचार करता है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, यह केवल जूट की बात नहीं है, सभी जो फैसले हैं, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है, उसमें यह कमीशन सभी बातों पर विचार करके ही एक सिफारिश करता है और वह सिफारिश भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को मिलने के बाद उसको सभी राज्य सरकारों की टिप्पणी के लिए भेजा जाता है। जब राज्य सरकारों की इससे संबंधित जो टिप्पणी आती है तो फिर भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालय की जो कमेटी है उसमें चर्चा होती है और सरकार द्वारा विचार करके फिर इसकी घोषणा की जाती है। यह जो प्राइस है, यह सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सिफारिश होती है और विचार करके ही घोषणा की जाती है। तो यह कहना कि यह बहुत कम है। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं, पर यह तो सभी पहलुओं पर विचार करके किया जाता है, इसलिए यह 470/- रुपए क्विंटल जो रखा गया है, मैं समझता हूं कि वह सभी पहलुओं पर विचार करके ही किया गया है।

दूसरी जो बात कही गई है कि एक ही किस्म के जूट का जो न्यूनतम मूल्य घोषित किया गया है, वह क्यों किया गया है यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा ही ऐसा होता रहा है। चूंकि यह टीडी–5 जो ग्रेड है, वह सबसे प्रचलित और पापुलर किस्म है और बाकी किस्मों के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि यह जो आपकी टैक्सटाइल कमीशन है, वह करता है। कुछ और भी वेरायटी हैं, लेकिन सबसे पापुलर वेरायटी जूट की यही है, जो कि बोया जाता है इस देश के भाग में। ...(व्यवधान)... इसीलिए बाकी जो एक्सरसाइज होती है वह कमीशन के द्वारा होती है। यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है। तो यह एक किसम की, जो पापुलर किस्म है, वह करके बाकी कमीशन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो बाजार में... (व्यवधान)...कीमत है, उसको लेकर तुलना करके फिर उसको तय करे। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) एक सेकेण्ड मंत्री जी, कुछ आवाजें एक साथ आ रही हैं। कई आवाजें आ रही हैं। ...(व्यवधान)...चलिए, जो भी है ठीक हो जाएगा।

श्री अरबिन्द नेताम: यहां तक उत्पादन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। उत्पादन के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जूट का सब्सिच्यूट भी तैयार कर लिया गया है, इसलिए भी जो दुनिया में मांग होती है, वह कम हो रही है। इसलिए इसका केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में जूट के उत्पादन में इसका असर हो रहा है। फिर भी जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, पिछली बार जो प्राक्योरमेंट हुआ है जूट कारपोरेशन की तरफ से पिछले तीन साल में, 1991 में 6.74 लाख बेल्स 1991–92 में 5.54 लाख बेल्स और लास्ट ईयर 1992–93 में 7.37। तो इस प्रकार से लास्ट की तुलना में, 1990–91 के कम्पेरिजन में जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ने ज्यादा ही प्रोक्योरमेंट किया है। तो इस प्रकार

से यहां तक कि पूरी सपोर्ट दी जाती है जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को ताकि अगर सपोर्ट न्यूनतम प्राइस से, समर्थन मूल्य से अगर कम फाइनल होता है तो उसको खरीदने की जिम्मेदारी जूट कारपोरेशन आफ इंडिया की है और भारत सरकार की ओर से उसको पूरी मदद की जाती है। तो इस प्रकार से एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि देर क्यों हुई, मैं माननीय सदस्य के विश्वास में कहता हूं कि कुछ देर हुई है समर्थन मूल्य की घोषणा करने में, केवल जूट के मामले में ही पिछले कुछ सालों में अक्सर देरी होती रही है और अभी हम एक प्रयोग किए हैं कि राज्यों को जो टिप्पणी के लिए, कमेंट्स के लिए भेजते हैं, अब हम कर रहे हैं कि सब राज्यों की मीटिंग एक दिन बुलाकर के, सूचना देकर के कमेंट्स न मंगाकर के केवल दिल्ली में उसकी मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो समय काफी जाया होता है, उसकी बचत हो सके और समय पर इसकी घोषणा की जा सके। कुछ देरियां तो हमें सीएपीसी की तरफ से भी और जो कुछ फारमेलिटीज हैं, विभिन्न राज्यों से और भारत सरकार से भी चर्चा हुई है, उस कारण से भी देरी हुई है, मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ऐसी देरी न हो। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि कुछ इस संबंध में जो प्रक्रिया है, उसमे बदलाव करने की... (व्यवधान)...

श्री सोमपाल : मंत्री जी, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित रूप से घोषित होने के लिए तारीख तय की गई है, उनका कैलेंडर बना हुआ है और आपकी वार्षिक रिपोर्टों में और दूसरी जगह निश्चित है कि गेहूं का मूल्य आप बुआई के एक महीना पूर्व घोषित करेंगे, धान का इतनी तारीख को करेंगे, उसकी तिथि निश्चित है। तो जब उनके विषय में तिथि निश्चित है तो जूट के विषय में विलम्ब क्यों है? उसको कैलेंडर में आप लाए हैं या नहीं लाए हैं और अगर लाए हैं तो उसको आप एडहियर क्यों नहीं करते?

श्री अरविन्द नेताम : प्रोसिजर की मैं बात करता हूं।

श्री सोमपाल : माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही ढीला जवाब है और उनकी गंभीरता इससे बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होती। निश्चित रूप से जब सब चीजों के समर्थन मूल्य घोषित करने का एक पंचांग निश्चित किया गया है तो इसे क्यों नहीं करते? मैं माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि जब सभी का है तो जूट का क्यों नहीं? अगर ढील होती है तो सरकार किस लिए है? हमेशा से अगर खराब होता रहा तो आप उसको क्या डिसकांटीन्यू नहीं करेंगे, इसी प्रकार की ढील चलती रहेगी?

श्री अरविन्द नेताम : जो प्रक्रिया है उसके कारण से ही देरी होती है और उसका भी निदान, जैसा मैंने कहा कि सारे राज्यों को कमेंट्स के लिए जो भजते हैं... (व्यवधान)...

श्री सोमपाल : वह तो आप सारी चीजों के लिए करते ह। ... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम : स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल रह हैं, लेकिन कैलेंडर आपका अपना है।

†[جناب محمد سلیم: اسٹیٹ گورنمنٹ پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں لیکن کیلنڈر آپ کا اپنا ہے۔]

श्री अरविन्द नेताम : हम तब्दीली कर रह हैं और उससे भी फर्क आ जाएगा और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, मैं यह बात कह रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं आपको।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सवाल यह है कि अगर ये कह रहे हैं, जो कुछ हुआ, तो वह हुआ, अभी भी क्या कोई टारगेटिड डेट है कि इस टाइम

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री दीपांकर मुखर्जी]

तक, इस महीने में हम लोग जूट का प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स कर देंगे या इस टाइम तक हम जूट कारपोरेशन को वर्किंग केपिटल देंगे ताकि वह जूट खरीद सके? कुछ टाइम, प्लानिंग, कुछ शेडयूल है क्या ? शैडयूल से ठीक हो सकता है, लेकिन शैडयूल है क्या ?

श्री अरविन्द नेताम : जितने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आइटम्स हैं, सबका शैडयूल फिक्स है, पर प्रोसिजर के कारण कुछ देरी होती है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What is the time? What is the calendar?

श्री अरविन्द नेताम : इसका जनवरी है, जूट का जनवरी है। तो इस प्रकार से..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद सलीम : आज मई हो गया, करीबन चार महीने ज्यादा हो गए। ..(व्यवधान)..

†شری محمد سلیم : آج مئی ہو گیا۔ قریباً چار مہینے زیادہ ہو گئے۔

SHRI SOM PAL: Madam Vice-Chairman, the rationale behind a fixed caten-dar for declaring or announcing the minimum support price is that the farmer should be able to decide the acreage to be allotted to the respective crop... *(Interruptions)*,..

SHRI MD. SALIM; Madam, it is quite obvious... *(Interruptions)*...

SHRI SOM PAL: That opportunity has already been missed.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : मंत्री जी, सवाल बहुत स्पेसिफिक है। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने साफ सवाल पूछा है। कलेंडर आपने तैयार किया है, उस हिसाब से आप सपोर्ट प्राईस कब तक तय करेंगे? तो आप यह बतावें।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI SOM PAL: Madam Vice-Chair-man, I wish to repeat the rationale: The rationale behind declaring or announcing the minimum support price is that the farmer should be allowed to allot his own acreage with reference to the prices for various crops and that should be done one month in advance before the sowing season starts. If this is so, it means that you have denied the farmer the opportunity to allocate a proper acreage to this crop and this shows the cavalier attitude of the Government towards this crop... *(Interruptions)*...

SHRI ARVIND NETAM: Madam Vice-Chairman, I say that there is a delay; I admit it. Due to procedural formalities there is a delay, but we are changing that system so that in future that calendar should be maintained. I assure that.

SHRI SOM PAL: Next year onwards?

SHRI ARVIND NETAM; Yes, yes. I assure the hon. Members and the hon. House that from next year or next season onwards, whatever the item may be,—not only jute—that calendar will be maintained. In every item, it will be maintained; that is my assurance. ... *(Interruptions)*...

SHRI MD. SALIM: I asked a specific question. Though it does not come under his Ministry, it is linked with jute. What is the allocation or the bugetary support for JCI?

SHRI ARVIND NETAM: I don't have the figures but I can supply them to the hon. Member.

SHRI SOM PAL: Madam Vice-Chairman, he has not given the figure of shrinking of acreage. Whether the acreage has shrunk or not, whether the production has gone down or not, whether the research has been lacking or not. whether the procurement programme was paralysed or not—to all these things he has not replied.

SHRI ARVIND NETAM: That information is not with me just now but that information I can supply to the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): We have another agenda before us. The hon. Railway Minister is going to make a *suo motu* statement.

Accident at Unmanned Leved Crossing involving 7208 Tangbhandra Express on South Central Railway on 5-5-1994

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Madam, with great anguish I have to again apprise the House—only the other day, I reported an earlier accident on which there was a discussion and there were clarifications—of an unfortunate mishap involving train No. 7208 Mahbubnagar-Secunderabad Tungbhadra Express and a jeep at about 18.10 hrs. on 5.5.1994 on the Mahbubnagar-Secunderabad Broad Gauge Single Line section of South Central Railway. While the train was on its journey in the block section between Gollapalli and Balanagar stations and nearing the unmanned level crossing No. 39 at km. 78/1, a jeep carrying a group of persons got hit by the train engine. Consequently, 13 persons travelling in the jeep, including five children, died and 3 others sustained injuries. The driver of the jeep was grievously hurt and was admitted in Mahbubnagar Civil Hospital alongwith another injured occupant of the jeep. One injured child is recovering in Jad-cherla Government Hospital. The train engine crew and passengers remained un-affected .

On receipt of the information about the accident, Medical Relief Train with a team of railway doctors was rushed to the site of accident from Secunderabad. Additional General Manager, Chief Safety Officer, South Central Railway, alongwith other senior officers and Additional Divisional Railway Manager, Hyderabad, proceeded to the site and later visited the hospitals.

It is also to apprise the House that Divisional Safety Officer of Hyderabad Division was travelling on the locomotive of the train as a part of his inspection schedule, Aoccrding to his report the ill fated jeep first slowed down and then in a quick action picked up speed resulting into a collision of the train engine and the rear portion of the jeep. Another jeep, which was closely following the first one, stopped well short of ths level crossing.

The unmanned level crossing, whore the accident occurred, is on a straight track and serves a village unmetalled road. The level crossing is equipped with whistle boards for trains, speed breakers and stop boards for road users. The unobstructed visibility both for train and road users is over 1000 metres.

Ex-gratia payment has been made to the next of kin of the identified dead and injured persons. An inquiry into the incident by a Committee of Senior Administrative Grade Officers has been ordered.

All railway workers and I express our deep condolences to the families who lost their relatives in this unfortunate incident
and also express sincere sympathies to
the injured.

I trust the House will join me in ex-tending heartfelt condolences to the bereaved families.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): This has happened in my State, I raised this point this morning during Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Do you want to seek clarifications?

DR. P. ALLADI RAJKUMAR: Yet, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA):, Okay.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Madam, these crocodile tears will not console the poor, mnocent families who lost their dear ones I,.once again, earnestly .appeal, to the hon. Minister to visit the sits because within70 hours two incidents occurred and nearly 50 people lost their